

Daily Current Affairs in Hindi 21 November 2018

भारत और राज्यों से संबंधित वर्तमान मामले

मरीजों ने 'सभी के लिए वहनीय, गुणवत्ता दवाएं' सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल के तहत 15,000 करोड़ रुपये बचाए

- पूरे देश में मरीजों ने 'सभी के लिए वहनीय, गुणवत्ता दवाएं' सुनिश्चित करने की सरकार की पहल के तहत करीब 15,000 करोड़ रुपये बचाए हैं।
- संघ के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने छत की कीमतों के निर्धारण और आवश्यक और जीवन रक्षा दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों का निर्धारण किया है। इसके परिणामस्वरूप रोगियों ने तब से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।
- कोरोनरी स्टेंट की छत की कीमतों के निर्धारण के बाद से लगभग 10 लाख हृदय रोगियों को 8,000 करोड़ रुपये बचाए जा रहे हैं।
- घुटने के प्रत्यारोपण के मूल्य निर्धारण के बाद लगभग 1.5 लाख घुटनों के रोगियों ने 2,000 करोड़ रुपये बचाए।
- मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने में एक बड़ा कदम है कि कोई भी नागरिक सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं की कमी के कारण पीड़ित नहीं है।

1993 से सिक्किम में वन आवरण को 4 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया है: मुख्यमंत्री

- राज्य के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के मुताबिक सिक्किम में जैव विविधता को संरक्षित करने और पर्यावरण अनुकूल नीति को अपनाने जैसे जैव विविधता को बचाने के लिए पहलों की एक बड़ी संख्या ने 1993 से अपने वन कवर में चार प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की है।
- छोटे उत्तर-पूर्वी राज्य में हरा कवर 2017 में 47.62 प्रतिशत बढ़कर 1993 में 43.9 5 प्रतिशत हो गया।
- राज्य जन जागरूकता और आवश्यक कानून फैलाने से जैव विविधता को संरक्षित करने के बारे में "बहुत प्रतिबद्ध" है।
- सिक्किम, देश के भौगोलिक क्षेत्र के केवल 0.2 प्रतिशत को कवर करता है, इसमें जबरदस्त जैव विविधता है और यह वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है।

गुजरात ने गिर शेरों को बचाने के लिए गहन परियोजना शुरू की

- 20 नवंबर, 2018 को गुजरात सरकार ने गिर शेरों के संरक्षण के लिए 351 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की। परियोजना कैनिन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) प्रकोप की पृष्ठभूमि में लॉन्च की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि 23 एशियाई शेर सौराष्ट्र में अपने एकमात्र निवास गिर राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं।
- इस गहन परियोजना में 108 आपातकालीन सेवाओं के समान आपातकालीन एम्बुलेंस वैन भी शामिल होगी।
- गुजरात सरकार ने गिर क्षेत्र में 10 किलोमीटर दूर पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में गिर क्षेत्र में 10 खानों को पकड़ने की मंजूरी दे दी है।

- वन्यजीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि शेर अभयारण्य के आसपास खनन और वाणिज्यिक गतिविधियां जंगली जानवरों के शांत अस्तित्व के लिए तेजी से खतरा बन गई हैं।

पश्चिम बंगाल ने संलग्न निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए बिल पास किया

- पश्चिम बंगाल के निवासियों के निवासियों के लिए अनिश्चित भविष्य के एक युग को समाप्त करने के लिए, डब्ल्यूबी असेंबली ने सर्वसम्मति से उत्तर बंगाल में निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए एक बिल पारित किया।
- भूमि भूमि और भूमि सुधार राज्य मंत्री चंडीमा भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2018, को सदन में विस्थापित किया गया था।
- डब्ल्यूबी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे "ऐतिहासिक विधेयक" कहा था, जो सभी नागरिक सुविधाओं और नागरिकता अधिकारों के साथ-साथ भारत के नागरिकों के रूप में पूर्ण निवासियों को पूर्ण स्थिति पाने में मदद करेगा।
- 1 अगस्त, 2015 को भारत और बांग्लादेश ने विश्व के सबसे जटिल सीमा विवादों में से एक को समाप्त कर दिया जो स्वतंत्रता के बाद से सात दशकों तक कुल 162 enclaves का आदान-प्रदान करके समाप्त हो गया था।
- इस विनिमय के साथ, 51 बांग्लादेशी enclaves में रहने वाले 14,856 लोग भारत का हिस्सा बन गए।
- उनके देश के लिए भारतीय कर्मों ने आज तक उन्हें दूर कर दिया, जिससे उनके लिए भूमि खरीदने, बेचने या खेती के लिए असंभव बना दिया गया।

वित्त से संबंधित वर्तमान मामले

आईआरडीएआई इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस हिस्सेदारी बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देता है

- बीमा नियामक ने यूके स्थित कानूनी और सामान्य समूह के लिए भारत की प्राथमिक इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिनकस एलएलसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सैद्धांतिक जीवन बीमा कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, दो सूत्रों ने पुष्टि की।
- इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा (जिसमें 44 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग है), आंध्र बैंक (30 फीसदी) और कानूनी और सामान्य के बीच संयुक्त उद्यम है। कानूनी और सामान्य ने जून में घोषणा की कि वह लाइफ इंश्योरेंस में वॉरबर्ग पिनकस को 7.1 अरब रुपये के लिए 26 फीसदी हिस्सेदारी बेच देगा।
- एक स्रोत ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को शेयर हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी में पुष्टि की।

भारत डब्ल्यूटीओ से स्टील, एल्यूमीनियम पर उच्च आयात शुल्क के लिए अमेरिका के खिलाफ पैनल स्थापित करने को कहा

- अमेरिका के साथ भारत का व्यापार विवाद विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अगले स्तर तक पहुंच गया है, क्योंकि भारत ने डब्ल्यूटीओ से संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एल्यूमीनियम और कुछ इस्पात उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए एक पैनल बनाने के लिए कहा था।
- भारत के डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारे तंत्र के तहत द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया में इस मुद्दे को हल करने में विफल होने के बाद पैनल स्थापित करने के लिए डब्ल्यूटीओ से आग्रह करने का आग्रह किया गया।

- इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस्पात आयात पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% लगाए गए टैरिफ लगाए थे। टैरिफ लगाते समय, अमेरिका ने यह कहकर उचित ठहराया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसलिए यह डब्ल्यूटीओ नियम के तहत 'सुरक्षा' है और डब्ल्यूटीओ के अनुमोदन से परे है।
- उच्च आयात शुल्क के इस लगाव ने इन उत्पादों के भारतीय कारोबार के निर्यात को प्रभावित किया। और भारत का मानना है कि अमेरिकी कदम वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुपालन में नहीं है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में सालाना \$ 1.6 बिलियन के स्टील और एल्यूमीनियम सामान निर्यात करता है।

नियुक्तियों से संबंधित वर्तमान मामले

अभिजीत बोस को व्हाट्सएप इंडिया प्रमुख नियुक्त किया गया

- मेसेंजर ऐप व्हाट्सएप ने अभिजीत बोस की नियुक्ति की घोषणा व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख के रूप में की। बोस कैलिफ़ोर्निया के बाहर व्हाट्सएप की पहली पूर्ण देश टीम का निर्माण करेगा और गुडगांव में स्थित होगा।
- बोस और उनकी टीम अपने ग्राहकों के साथ बड़े और छोटे दोनों व्यवसायों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इस साल की शुरुआत में, व्हाट्सएप ने छोटे व्यवसाय मालिकों और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जारी किया ताकि ग्राहकों के साथ बड़े व्यवसायों को पूरा किया जा सके।
- आज, भारत में इन व्हाट्सएप व्यापार उत्पादों के दस लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

एयरएशिया इंडिया ने पूर्व इंडिगो सीओओ संजय कुमार को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नामित किया

- बजट यात्री वाहक ने बुधवार को कहा कि विमानन उद्योग के अनुभवी और पूर्व इंडिगो मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी संजय कुमार को एयरएशिया इंडिया के नए मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 3 दिसंबर से प्रभावी है।
- एयरलाइन के अनुसार, कुमार एयरलाइन के वाणिज्यिक संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे और नए नियुक्त सीईओ और एमडी सुनील भास्करन को रिपोर्ट करेंगे।

सॉफ्टबैंक ने नॉर्वे के सुमेर जुनेजा को भारत के संचालन के लिए नियुक्त किया है

- भारत के सबसे शानदार स्टार्ट-अप निवेशक, सॉफ्टबैंक ने देश में करीब 8 अरब डॉलर (570 अरब रुपये) की कमाई की है।
- बुधवार को, यह घोषणा की गई कि उद्यम पूंजीपति सुमेर जुनेजा अपने 100 अरब डॉलर के विजन फंड की स्थानीय शाखा का नेतृत्व करेंगे।
- जापानी फर्म ने यह भी कहा कि यह मुंबई में अपना पहला भारत कार्यालय खोल देगा, क्योंकि यह इस क्षेत्र में अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों का बेहतर समर्थन करने और आगे बढ़ने के लिए दिखता है।

सुब्रमण्यम जंबुननाथ को श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया

- श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ने बुधवार को कहा कि उसने सुब्रमण्यम जंबुननाथ को अपनी आवास वित्त सहायक कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है।
- 20 नवंबर, 2018 को आयोजित बैठक में बोर्ड ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम जंबुननाथ को नियामक फाइलिंग में कहा, श्रीराम सिटी यूनियन ने नियामक फाइलिंग में कहा।

विश्व से संबंधित वर्तमान मामले

वजन और माप पर 26 वें सामान्य सम्मेलन में किलोग्राम की मानक परिभाषा को फिर से परिभाषित की गई

- वजन और माप (सीजीपीएम) पर सामान्य सम्मेलन की 26 वीं बैठक नवंबर 13-16, 2018 से फ्रांस के वर्साइल्स, पालिस डेस काँग्रेस में आयोजित की गई थी। सटीक और सटीक माप के लिए सीजीपीएम दुनिया का सबसे ऊंचा अंतरराष्ट्रीय निकाय है।
- 26 वां सीजीपीएम विशेष और ऐतिहासिक था, क्योंकि सदस्यों ने मौलिक प्लैंक के निरंतर (एच) के संदर्भ में 130 वर्षीय "ले ग्रैंड के - एसआई इकाई की किल इकाई" की पुनर्वितरण के लिए मतदान किया था। 20 मई, 2019 को नई परिभाषा लागू होगी।
- सीजीपीएम में 60 देशों और भारत सहित 42 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के निदेशक डी के असवाल और एनपीएल की योजना, निगरानी और मूल्यांकन टीडी सेनगुत्तुवन के प्रमुख ने किया था।
- सीजीपीएम के मुख्य कार्यकारी निकाय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय (बीआईपीएम) अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ यूनिट्स (एसआई) को परिभाषित करने की ज़िम्मेदारी है।
- एसआई का संशोधन राष्ट्रीय मेट्रोलोजी संस्थानों (भारत के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला) और बीआईपीएम के बीच कई वर्षों के गहन वैज्ञानिक सहयोग की समाप्ति है।

ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र प्रवास समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया

- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 21 नवंबर, 2018 को घोषणा की कि वह माइग्रेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, यह कहकर कि समझौता इसकी मौजूदा आप्रवासन नीतियों को कम करेगा।
- निर्णय पर बोलते हुए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि सरकार का मानना है कि कॉम्पैक्ट अपनी अच्छी तरह से स्थापित नीतियों के साथ असंगत है, न कि ऑस्ट्रेलिया के हित में।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार, देश की आप्रवासन नीति पहले ही सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देती है।
- इसलिए, सरकार का मानना है कि समझौते को अपनाने से ऑस्ट्रेलिया में अवैध प्रवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है और लोगों के तस्करी व्यापार का मुकाबला करने में कठोर सफलताओं को उलट दिया जाएगा।

यूएन पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने यात्रा खर्च पर हिसाब-किताब की जांच के दौरान इस्तीफा दे दिया

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने 20 नवंबर, 2018 को अपने विशाल यात्रा व्यय पर सवाल उठाते हुए एक हिसाब-किताब की जांच रिपोर्ट के बाद अपनी पद से इस्तीफा दे दिया।
- एक आधिकारिक बयान में, सोलहेम ने कहा कि उन्हें अपने यात्रा व्यय की अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट मिली है और गहरे प्रतिबिंब के बाद, उन्होंने कदम उठाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र के एक लेखा परीक्षा में पाया गया था कि सोलहेम ने यात्रा पर लगभग पांच लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे।
- इन अन्यायपूर्ण यात्रा खर्चों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण प्रमुख ने पर्यावरण के लिए थोड़ा सम्मान और हवाई यात्रा द्वारा उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को दिखाया। वे ऐसे समय में आते हैं जब विश्व निकाय बजट को कम करने के साथ संघर्ष कर रहा है।

सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात ने यमन के युद्ध में 500 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की

- 20 नवंबर, 2018 को यमन में हुथी विद्रोहियों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अकाल के कगार पर देश को 500 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की।
- 10 मिलियन से अधिक लोगों का समर्थन करने के लिए खाद्य संकट के जवाब में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात प्रत्येक 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे।
- दान संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय सहायता समूहों के माध्यम से भी जाएंगे।

अमेरिका ने पाकिस्तान को 1.66 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी है

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को 1.66 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देशों पर निर्णय लिया गया है।
- पिछले ओबामा प्रशासन के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के लिए उप सहायक सचिव रक्षा, डेविड सेडनी ने कहा कि इस साल जनवरी में शुरू हुई सैन्य सहायता को अवरुद्ध करना अमेरिकी निराशा का एक मजबूत संकेत है।
- उन्होंने कहा कि अब तक पाकिस्तान ने अमेरिकी अमेरिकी चिंता को हल करने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं कि पाकिस्तान अक्सर उन समूहों को प्रोत्साहित करता है जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ हिंसा का उपयोग करते हैं।

खेल से संबंधित वर्तमान मामले

भारतीय जिमनास्ट्स ने एक्रोबेटिक जिमनास्टिक वर्ल्ड कप में दो कांस्य पदक जीते

- भारतीय जिमनास्ट्स ने बाकू में फिग एक्रोबेटिक वर्ल्ड कप के पुरुषों और महिलाओं के समूह कार्यक्रमों में दो कांस्य पदक जीते।
- प्रिंस एरिस और रेजीलेश सुरिबाबू ने दो दिवसीय आयोजन में 20.560 रन बनाने के बाद तीसरे स्थान पर रहे और राष्ट्रीय जिमनास्टिक एरिना में कांस्य पदक जीता।

- अयोधी गोडसवार, प्राचीपार्खी और मृणमयी वाल्दे की भारतीय महिलाओं के तीनों ने भी 18.200 के स्कोर के बाद ग्रुप इवेंट में कांस्य पदक जीता।

आईसीसी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मुआवजे का दावा खारिज कर दिया

- 20 नवंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने के लिए समझौते का सम्मान करने से इंकार कर पाकिस्तान द्वारा मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया।
- आईसीसी ने एक बयान में कहा कि तीन दिवसीय सुनवाई के बाद, विवाद पैनल ने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडल (बीसीसीआई) के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के दावे को खारिज कर दिया है।
- समझौता ज्ञापन पर केंद्रित विवाद जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2015 और 2023 के बीच छह द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने के लिए सहमत हुए थे। पीसीबी ने 70 मिलियन डॉलर का मुआवजा दावा किया था।

दिन से संबंधित वर्तमान मामलों

वैश्विक टेलीविजन दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया

- विश्व टेलीविजन दिवस 2018 21 नवंबर, 2018 को मनाया गया था।
- वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2018 का विषय "लाइट्स, कैमरा, एसडीजी पर एक्शन: परिवर्तन बनाने के लिए कहानी कहने की शक्ति" था।